जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 316 प्रभात चूरू, सोमवार 16 मार्च, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

केरल, असम, पुडुचेरी में 9 अप्रेल, तमिलनाडु 23 तथा प.बंगाल में 23 व 29 को मतदान

सभी राज्यों में मतगणना 4 मई को, आदर्श आचार संहिता लागू

- मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाँच राज्यों में 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 824 विधानसभा सीटों में 2.19 लाख मतदान केन्द्र बनेंगे तथा करीब 25 लाख चुनावकर्मी तनाव होंगे।

नई दिल्ली, 15 मार्च। चुनाव आयोग ने रविवार को देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इसके तहत पुडुचेरी, केरल और असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। वहीं, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा, जिसमें 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज शाम 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि संबंधित पांच राज्यों में लगभग 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए 824 विधानसभा सीटों पर करीब 2.19 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए लगभग 25 लाख चुनाव कर्मी तैनात किए जाएंगे।

आयोग के मुताबिक, पांचों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म होगा, जबकि तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई तक है। असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई और केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को समाप्त होगा। वहीं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा का कार्यकाल 15 जून तक है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।

निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान कराया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में शेष 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

पश्चिम बंगाल में पिछली बार 2021 का विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड आठ चरणों में हुआ था, जिसमें कई जगह हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं। इससे पहले 2016 और 2011 में छह चरणों में मतदान हुआ था, जबकि 2006 में पांच चरणों में चुनाव कराए गए थे। 2001 के बाद से राज्य में एक ही दिन मतदान नहीं हुआ है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 2011 से सत्ता में है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी ने 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन को समाप्त किया था। 2011 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 184 सीटें, कांग्रेस को 42 सीटें, वाम दल को 40 सीटें मिली थीं। इसके बाद भाजपा ने राज्य में धीरे-धीरे अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की।

इसके बाद 2016 के चुनाव में भाजपा को 3 सीट तथा 2021 में भाजपा को 77 सीटें मिली थीं। वहीं, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती थीं, जो बाद में उपचुनाव जीतकर 215 हो गईं।

2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीती थीं। हालांकि, 2024 में यह संख्या घटकर 12 रह गई।

चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर भी विवाद जारी है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लगभग 63 लाख नाम हटाए गए हैं और करीब 60 लाख मतदाताओं को ''विवादाधीन'' श्रेणी में रखा गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, जबकि भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में है। वाम दल और कांग्रेस भी अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश में हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

देश की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा

नई दिल्ली, 15 मार्च। चुनाव आयोग ने चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी राज्यों में मतदान अप्रैल के महीने में होंगे। इसके साथ ही छह राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी किया गया है। महाराष्ट्र की दो गुजरात की एक विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं, गोवा, नागालैंड और त्रिपुरा की एक-एक सीट उपचुनाव होना है।कर्नाटक में दो सीटों पर उपचुनाव होंगे। ये सभी सीटें तत्कालीन विधायकों

- गोवा, कर्नाटक, नागालैंड व त्रिपुरा में मतदान 9 अप्रेल को तथा महाराष्ट्र व गुजरात में 23 अप्रेल को होगा।

के निधन से खाली हुई हैं। चुनाव आयोग के अनुसार उपचुनाव दो चरण में होंगे।गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में पहले चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं, महाराष्ट्र और गुजरात में दूसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है।

अजित पवार की बारामती सीट पर दूसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। अजित पवार के निधन के बाद उनकी जगह उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली सुनेत्रा पवार का इस सीट से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इज़रायल को बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी महसूस होने लगी

अमेरिका के पास पर्याप्त भंडार है, पर अभी स्पष्ट नहीं कि वह इज़रायल को देगा या नहीं

- पिछले साल गर्मियों में ईरान के साथ हुई झड़पों में बड़ी संख्या में इन्टरसेप्टर इस्तेमाल हो गये थे। इस कारण से उसकी लम्बी दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली पर पहले ही दबाव था। मौजूदा संघर्ष में ईरान के लगातार हमलों ने इस दबाव को और बढ़ा दिया।

तेल अवीव/वॉशिंगटन, 15 मार्च। पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव के बीच इज़रायल की मिसाइल रक्षा क्षमता पर दबाव बढ़ ता दिख रहा है। ईरान की तरफ लगातार हो रहे हमलों के कारण इज़रायल के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी होने लगी है।

बताया जा रहा है कि इज़रायल ने इस स्थिति को लेकर अमेरिका को आगाह किया है, जबकि वॉशिंगटन का कहना है कि उसके अपने भंडार फिलहाल पर्याप्त हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका अपने इंटरसेप्टर इज़रायल को बेचेगा या साझा करेगा।

समाचार समूह टाइम्स ऑफ इज़रायल ने अमेरिकी समाचार वेबसाइट सेमाफोर के हवाले से बताया है कि पश्चिम एशिया में बीते 15 दिनों से जारी संघर्ष के बीच इज़रायल को अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए जरूरी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इज़रायल ने इस हफ्ते अमेरिका को जानकारी दी है कि लगातार हो रहे हमलों के कारण उसके इंटरसेप्टर का भंडार तेजी से घट रहा है।

वहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि, अमेरिकी अधिकारियों को पहले से पता था कि इज़रायल पहले से ही सीमित इंटरसेप्टर स्टॉक के साथ इस संघर्ष में उतरा था। पिछले साल गर्मियों में ईरान के साथ हुई झड़पों के दौरान बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर इस्तेमाल हो चुके थे, जिससे उसकी लंबी दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली पर पहले से दबाव था। मौजूदा संघर्ष के दौरान ईरान के लगातार हमलों ने इस दबाव को और बढ़ा दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान अब अपनी कुछ मिसाइलों में क्लस्टर गोला-बारूद भी जोड़ रहा है। इससे मिसाइलों को रोकने के लिए ज्यादा इंटरसेप्टर की जरूरत पड़ सकती है और इज़राइल की एयर डिफेंस प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका अपने इंटरसेप्टर इज़रायल को बेचेगा या साझा करेगा। ऐसा करने से अमेरिका के घरेलू भंडार पर भी दबाव पड़ सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इज़रायल के पास ईरानी मिसाइलों से बचाव के लिए अन्य विकल्प भी हैं, जिनमें लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल शामिल है। हालांकि लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर सबसे प्रभावी रक्षा प्रणाली माने जाते हैं। वहीं, इज़राइल की प्रसिद्ध आयरन डोम प्रणाली मुख्य रूप से कम दूरी के रॉकेट और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए बनाई गई है।

'मध्य पूर्व के देश अपने क्षेत्रों से अमेरिकी सेना हटाएं'

ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि विदेशी सेना की उपस्थिति मौजूदा क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाती है

- ईरान का कहना है कि अमेरिका लंबे समय से खाड़ी देशों को सुरक्षा देने का दावा करता रहा है, पर उसका सुरक्षा ढांचा कमज़ोर साबित हुआ है।

तेहरान, 15 मार्च। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्रों से अमेरिका की सेना को हटाने पर विचार करें। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में विदेशी सैन्य मौजूदगी क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा रही है।

अराघची ने कहा कि पूरे क्षेत्र में लगातार जवाबी हमले और सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे हालात और अधिक अस्थिर हो गए हैं। उनके अनुसार, ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों की सैन्य मौजूदगी शांति स्थापित करने के बजाय संकट को और गहरा कर सकती है।

ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका लंबे समय से खाड़ी देशों को सुरक्षा देने का दावा करता रहा है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह सुरक्षा ढ ांचा कमजोर साबित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी सुरक्षा नीति क्षेत्र में स्थिरता लाने में प्रभावी नहीं रही है।

अराघची ने यह दावा भी किया कि अमेरिका अब महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों, खासकर चीन से सहयोग की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति दिखाती है कि क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था में नई चुनौतियां सामने आ रही हैं।

ईरान ने अपने पड़ोसी देशों से अपील करते हुए कहा कि वे विदेशी सैन्य ताकतों को अपने क्षेत्रों से हटाने के बारे में गंभीरता से विचार करें, ताकि क्षेत्र में स्थिरता और शांति कायम की जा सके।

ओडिशा में 11 ईनामी माओवादियों ने सरेंडर किया

भुवनेश्वर, 15 मार्च। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभियान में ओडिशा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कालाहांडी जिला मुख्यालय भवानीपटना की रिजर्व पुलिस लाइन में रविवार को आयोजित विशेष कार्यक्रम में 11 हार्डकोर माओवादियों ने पुलिस महानिदेशक वाई बी खुरानिया के सामने हथियार डाल दिए।

- इन सभी पर कुल मिलाकर 63.25 लाख रूपए का ईनाम था।

आत्मसमर्पण करने वालों में नकुल नामक माओवादी भी शामिल है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की ओडिशा राज्य समिति का डिविजनल कमेटी सदस्य था और जिस पर 22 लाख रुपये का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले समूह में एक डिविजनल कमेटी सदस्य, पांच एरिया कमेटी सदस्य और पांच पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन सभी पर कुल मिलाकर 63.25 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजीपी ने आश्वासन दिया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

मुख्यमंत्री ने वित्तमंत्री सीतारमण से मुलाकात की

नई दिल्ली/जयपुर, 15 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने पूंजीगत निवेश हेतु राज्य को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत मिल रहे

- उन्होंने राजस्थान को विशेष सहायता योजना के तहत मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त किया।

सहयोग के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया।

विकसित राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री और केन्द्रीय वित्त मंत्री ने प्रदेश के चहुंमुखी विकास, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं आधारभूतढ ांचे के विषय परविस्तृत बातचीत की।

''नेतन्याहू ठीक हैं'' : इज़रायल ने उनकी मौत की खबर को फर्जी बताया

युद्ध को लेकर नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो के बाद सोशल मीडिया में उनकी मौत की खबर फैली

- सोशल मीडिया यूजर्स के अनुसार, वीडियो में नेतन्याहू के दाहिने हाथ में छह उंगलियां दिख रही हैं, इससे लगता है कि यह ए.आई. जनरेटेड है। इस कारण से इज़रायल के प्रधानमंत्री की मौत की चर्चा सोशल मीडिया में फैल गई।

नई दिल्ली, 15 मार्च। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निधन की बात कही जा रही है। इसको लेकर उनके ऑफिस ने बयान जारी कर कहा है कि वे ठीक हैं।

अनादोलू एजेंसी के एक संवाददाता ने दफ्तर से पूछा कि क्या उनके पास सोशल मीडिया पर बढ़ ते इन दावों पर कोई बयान है कि''नेतन्याहू की हत्या कर दी गई है।'' इस पर नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा, ''ये फर्जी खबरें हैं, प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक हैं।''

शुक्रवार को नेतन्याहू ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर किया था।

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि उन्होंने इस वीडियो में नेतन्याहू के दाहिने हाथ में छह उंगलियां देखी हैं, जिससे यह अफवाहें तेज हो गईं कि यह वीडियो एआई-जनरेटेड है।

वीडियो में जब नेतन्याहू अपने हाथ ऊपर उठाते हैं तो छोटी उंगली के बगल में मांस का एक अतिरिक्त टुकड़ा दिखाई देता है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि यह छठी उंगली थी।

अमेरिकी रूढ़ि वादी राजनीतिक टिप्पणीकार कैडिस ओवेन्स ने पूछा, ''बीबी कहां हैं?'' उन्होंने लिखा, ''ध्यान दें कि पूरे वीडियो में ब्लैकआउट पर्दा बिल्कुल एक ही पैटर्न में कैसे हिल रहा है, ऐसा लगता है जैसे यह लूप में चल रहा हो। जबकि दोनों झंडे बिल्कुल भी नहीं हिलते। यह एआई का साफ संकेत है।''

हालांकि, इस दावे को एक अन्य यूजर ने खारिज कर दिया, जिसने कहा, ''आजकल कई लोग नकली बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि न्यूज ब्रॉडकास्टर। इसका मतलब यह नहीं है कि वह नकली है।''

पोप लियो ने सैन्य संघर्ष रोकने की अपील की

वेटिकन सिटी, 15 मार्च। पश्चिम एशिया में बढ़ ते तनाव और जारी सैन्य संघर्ष के बीच पोप लियो ने युद्धविराम की जोरदार अपील की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हालात बेहद गंभीर हैं और हिंसा को तुरंत रोककर संवाद का रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

- उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में लोग दो सप्ताह से युद्ध की भयावहता झेल रहे हैं।

रविवार को वेटिकन सिटी में एंजेलस प्रार्थना के बाद अपने संबोधन में पोप ने कहा कि खाड़ी देशों में लोग पिछले दो सप्ताह से युद्ध की भयावहता झेल रहे हैं। उन्होंने संघर्ष में शामिल पक्षों से अपील करते हुए कहा कि वे तुरंत संघर्ष विराम लागू करें और बातचीत के जरिए समाधान तलाशें।

पोप लियो ने कहा कि इस संघर्ष में हजारों निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की जिनके प्रियजन स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों में मारे गए।

'भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को दूर करे'

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने भारत से इस संबंध में आग्रह किया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 मार्च। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को ''ईरान का मित्र'' बताया है। लेकिन जिस बात को भारतीय मुख्यधारा का मीडिया कम महत्व दे रहा है, वह यह है कि तेहरान ने नई दिल्ली से आग्रह किया है कि ''ब्रिक्स'', जिसकी अध्यक्षता इस समय भारत कर रहा है, पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष को सुलझाने में ''मजबूत'' और ''रचनात्मक'' भूमिका निभाए, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्गों को प्रभावित कर रहा है।

भारत इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष है और यह ऐसा एकमात्र प्रमुख मंच है, जिसने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। ईरान 2024 से इसका सदस्य है और भारत अक्सर खुद को ''ग्लोबल साउथ'' की आवाज बताता है। समूह के अन्य संस्थापक सदस्य, ब्राज़ील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका व्यक्तिगत रूप से अमेरिका-इज़रायल के हमलों की निंदा कर चुके हैं।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस प्रस्ताव का सह-प्रायोजन किया है, जिसमें खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की गई है, लेकिन अमेरिका-इज़रायल द्वारा ईरान और लेबनॉन पर किए गए हमलों की आलोचना नहीं की गई। यह बात तेहरान ने साफ तौर पर और निश्चित रूप से नोट की है। संयुक्त बयान जारी करने में विवाद का मुख्य कारण ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच के मतभेद भी हैं।

ऊर्जा संकट को गहराई से महसूस कर रही मोदी सरकार ईरान से लगातार संपर्क करती दिखाई दे रही है। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची ने युद्ध शुरू होने के बाद गुरुवार शाम चौथी बार फोन पर बातचीत की। भारत की मुख्य चिंता यह है कि होरमुज़ स्ट्रेट के रणनीतिक समुद्री मार्ग से भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाज़ सुरक्षित रूप से गुजर सकें, जिसे तेहरान ने आंशिक रूप से अवरुद्ध कर दिया है। नई दिल्ली में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने शुक्रवार दोपहर पत्रकारों से कहा कि उनकी सरकार जल्द ही यह स्पष्ट कर देगी कि क्या भारत को होरमुज़ स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, जिसे ईरानी बलों ने अमेरिका-इज़रायल के हमलों के जवाब में बंद किया है। फतहाली ने कहा कि दो से तीन घंटे में और जानकारी दी जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारत इस स्थिति में और ''युद्ध के बाद'' ''विभिन्न क्षेत्रों में ईरान की ''मदद'' करेगा, हालांकि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया।

- ब्रिक्स ने ईरान वॉर के बारे में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, हालांकि, ब्रिक्स के सदस्य देश, ब्राज़ील, चीन, रूस, साउथ अफ्रीका आदि, ईरान पर अमेरिका-इज़रायल हमलों की व्यक्तिशः निंदा कर चुके हैं। जबकि भारत, जो ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 135 देशों में से एक है।
- ईरान के राष्ट्रपति ने भारतीय मीडिया पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान को मित्र बताया है, पर, भारतीय मीडिया तेहरान के इस आग्रह को दबा रहा है कि भारत को ब्रिक्स के मार्फत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना के लिए पहल करनी चाहिए।

कई जिलों में वर्षा, हनुमानगढ़ टपकूड़ा में ओले गिरे

- मौसम विभाग ने 18 से 21 मार्च के बीच आंधी व वर्षा की संभावना बताई।

जयपुर, 15 मार्च। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार को मौसम बदला हुआ नजर आया। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि हनुमानगढ़ और टपूकड़ा क्षेत्र में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 18 से 21 मार्च के बीच एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आंधी-बारिश की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 16-17 मार्च को मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इसके बाद 18 मार्च से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जोधपुर और बीकानेर संभाग में मेघगर्जन, आंधी और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)